

नव भारत



समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान

कृषि विकास से लेकर कृषकों के सम्मान तक
अन्नदाता के साथ राजस्थान सरकार



कृषि सुविधाओं का विस्तार

- 43,800 किलोमीटर कृषि भूमि की तारबंदी पर 482.46 करोड़ का अनुदान
- 72.36 लाख कृषकों को ₹122.66 करोड़ के निशुल्क बीज मिनीकट वितरित
- पीएम कुसुम कंपोनेंट बी में 67,408 सोलर पंप के सेट की स्थापना पर ₹1134 करोड़ का अनुदान
- 50 हजार कृषकों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रति कृषक ₹10 हजार की सहायता



कृषि विकास

- 35,893 हजार से अधिक खेत तलाई (फार्म पॉण्ड) का निर्माण
- खेत तलाई निर्माण पर ₹328 करोड़ का अनुदान
- लगभग 99 हजार किसानों को पाइपलाइन स्थापना पर अनुदान
- 10.85 लाख वर्गमीटर शेडनेट हाउस स्थापित

किसान सम्मान निधि

- ₹11,008 करोड़ से अधिक राशि किसानों को हस्तांतरित
- योजना के तहत लगभग 71 लाख से अधिक कृषक परिवार लाभान्वित
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹6000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹3000 वार्षिक की अतिरिक्त सहायता। इस प्रकार पात्र किसान परिवार को ₹9000 की वार्षिक आर्थिक सहायता

पशुपालन एवं डेयरी

- 1.03 लाख गोपालक परिवारों को ₹775 करोड़ तक ब्याजमुक्त ऋण
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 23.12 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा
- 1962 मोबाइल वेटेरिनरी सेवा से 64.17 लाख पशुओं का उपचार एवं 17.49 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में लगभग 5 लाख किसानों को ₹5 प्रति लीटर की दर से ₹1,401 करोड़ का अनुदान

गेहूं खरीद एवं बोनस

- गेहूं के समर्थन मूल्य ₹2,585 प्रति क्विंटल पर ₹150 अतिरिक्त बोनस
- वर्ष 2026-27 में 3.22 लाख किसानों से 27.12 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद, ₹407 करोड़ बोनस का भुगतान

फसल सुरक्षा

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ₹9,657 करोड़ के बीमा क्लेम वितरित
- खरीफ 2025 में देश में सर्वाधिक 2.19 करोड़ फसल बीमा पॉलिसियां

सहकारिता एवं भंडारण

- किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण ₹67 हजार करोड़ रुपए वितरित
- सहकारी समितियों के लगभग 10 लाख नए सदस्य बनाए गए
- 8,525 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण
- 1,955 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन
- गांवों में आधुनिक कृषि गोदामों का निर्माण
- 242 श्रीअन्न (मिलेट) उत्पाद आउटलेट्स की शुरुआत

राजस्व एवं किसान सुविधा

- राजस्व न्यायालयों में 5.63 लाख मामलों का निस्तारण
- ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लाखों राजस्व प्रकरणों का समाधान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान